पेज 1 का शेष भाग

चार माह में चार बार तबादला

फरीदाबाद (म.मो.) एनआईटी में करीब साढ़े तीन साल डीएसपी रह चुके दर्शन लाल मलिक का तबादला करीब चार माह पहले हरियाणा सशस्त्र पुलिस का हुआ था। सर्वविदित है कि उस बंजर तैनाती पर कोई जा कर राज़ी नहीं तो दर्शन लाल ही क्यों जायें, लिहाजा थोड़े दिन बाद उनका तबादला वापस इसी शहर में, लेकिन पुलिस आयुक्त कार्यालय में हो गया। इस तैनाती में दफ़्तर की डाक निकालने के अलावा और तो कोई काम होता नहीं, इसलिए यहां भी उनका दिल नहीं लगा तो उनका तबादला होडल का हो गया। लेकिन कहां फरीदाबाद, कहां होडल? लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लिहाज़ा कुछ दिन वहां भी काटे। अब अंतत: उनका तबादला बतौर एसीपी फरीदाबाद (सराय ख्वाजा) का हो जाने से उन्हें काफ़ी राहत होगी। लेकिन इसी पोस्ट पर दो माह पूर्व बड़ी मुश्किल से आईआरबी भोंडसी, जिसकी तैनाती आजकल जम्मू-कश्मीर में चल रही है, से जान छुड़ा कर आये नवीन सहगल को उठा कर एसीपी तिगांव व छांयसा लगा दिया गया। प्रश्न यह पैदा होता है कि सरकार को और कोई काम नहीं है क्या जो रोज़-रोज़ तबादलों पर ही लगी रहती है?

पुलिस की नीयत साफ़ हो तो हो ही नहीं सकते अपराध

अपराध एवं अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए जो ज़रूरी काम सरकार को करने चाहिएं, उन्हें न करके फ़िज़ूल की नाटकबाजियां वह करती रहती है, केवल इसलिए कि जनता को भ्रमित किया जा सके कि उसे अपराध-नियंत्रण की कितनी चिंता है। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली भी ऐसी ही एक नाटकबाजी बन कर रह गई है। असल में प्रणाली कोई बुरी नहीं होती, बुरा होता है उसे लागू करने का तरीका, उसे लागू करने वाले अफ़सर। पुरानी व्यवस्था में जहां ज़िले का काम काज एक एसपी व तीन-चार डीएसपी चलाते थे, नई व्यवस्था में वही काम एक आईजी, एक डीआईजी, छ: एसपी तथा दस डीएसपी करने लगे हैं। दूसरे शब्दों में, जहां ज़िले का काम काज चार-पांच अफ़सर देखते थे, वहीं अब 18 हो गये हैं। यानी कि कम से कम 12 अफ़सर बढ़ गये। ऐसे एक अफ़सर के साथ कम से कम 10-12 छोटे मुलाज़िम बतौर निजी स्टॉफ़ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार ज़िले में जहां पहले से ही मुलाज़िमों की कमी चल रही हो, वहां 125-150 मुलाज़िम और एक तरह से घट गये। इसके परिणामस्वरूप थानों व चौकियों में थानेदार तो मिल जायेंगे, लेकिन सिपाही के दर्शन नहीं होते। पीसीआर जिप्सी में जहां कम से कम चार मुलाज़िम होने चाहिए, वहां केवल दो (एक ड्राइवर और एक थानेदार) से काम टपाया जा रहा है।

कमिश्नरी प्रणाली के पक्षधरों का मानना है कि अफ़सरों की संख्या बढ़ने से छोटे मुलाजिमों की निगरानी कड़ी व मार्गदर्शन बेहतर हो जाने से अपराधियों पर नियंत्रण कड़ा होगा जिससे अपराधों में कमी आना निश्चित है। उदाहरण के लिए बल्लबगढ़ के पांच थानों को पहले जो एक डीएसपी देखता था, उन्हीं की देखभाल के लिए अब एक एसपी व दो डीएसपी हो गये हैं तथा इनके ऊपर एक डीआईजी और एक आईजी और हो गये। इस प्रणाली के तहत लगाये गये सभी पुलिस अधीक्षकों को किसी भी ज़िले के एसपी की तर्ज पर झंडी वाली कार भी दी गई, जिससे वे वास्तव में एसपी लग सकें। शुरू-शुरू में कुछ दिन तो जमे भी, लेकिन शीघ्र ही सारी पोल-पट्टी खुल गई कि ये तो नकली या दिखावटी एसपी हैं, असली पावर तो आईजी के हाथ में है।

ज़िले भर के सिपाहियों से लेकर इन्सपेक्टरों तक से काम लेने के लिए एसपी को व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनके द्वारा वह अपने अधीन इन मुलाज़िमों की नियुक्ति, बदली, सज़ा व ईनाम आदि जिसको जो मिलना चाहिए, वह देता है। उसकी सहायता एवं सहयोग के लिए चार-पांच डीएसपी होते हैं जो एसपी द्वारा प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करके उसके काम में हाथ बंटाते हैं। लेकिन अब छ: पुलिस अधीक्षकों व दस उप पुलिस अधीक्षकों के पल्ले कुछ भी नहीं, वे एक सिपाही तक का तबादला अथवा तैनाती कर पाने में असमर्थ हैं। ये सारे काम आईजी स्वयं करता है। इस महकमें में परवाह उसी की की जाती है जिसके पल्ले कुछ हो। जो किसी का न तो कुछ बना सके ना बिगाड़ सके, उसकी परवाह कोई करें भी क्यों? इन अफ़सरों को जब अपने ही ज़ोन में किसी मुलाज़िम को इधर से उधर कराने की जरूरत महसूस होती है तो ये अफ़सरान राजनेताओं का सहारा लेते हैं। जब एसपी स्तर के अधिकारी राजनेताओं के माध्यम से तबादले करायें तो मुलाज़िम सीधे ही राजनेताओं की शरण में क्यों न जायें? इसी के चलते प्राय: 'बढ़िया' तैनाती के लिए मुलाज़मान राजनेताओं के चक्कर लगाते रहते हैं। राजनेताओं द्वारा तबादले व तैनातियां कराना कुछ हद तक समझ में आता है, लेकिन जब यही काम एक शराब ठेकेदार के माध्यम से होने लगे तो माथा ठनकना स्वाभाविक है। जो ठेकेदार मुलाज़िमों के तबादले व तैनातियां करा सकने में समर्थ हो तो फ़िर उसके काले धंधों को पकड़ने की हिम्मत कौन करेगा?

जरायम बढ़ने के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण थाने और चौकियों की नीलामी है। जो मुलाज़िम किसी को एक मुश्त या मासिक कुछ देकर तैनाती पायेगा तो उसका ध्यान एवं प्राथमिकता कभी भी अपराध नियंत्रण पर नहीं हो सकता, उसका ध्यान सदैव दी गई एवं दी जाने वाली रकम को एकत्र करने पर ही रहता है, जिसके लिए वह सारे जतन करता है। कहने की जरूरत नहीं कि जो चौकी इंचार्ज अपने नियोक्ता को पैसे दे कर लगेगा, वह अपने एसएचओ की परवाह क्यों करेगा और जो एसएचओ इस तरह से लगा होगा, वह अपने डीएसपी की क्या परवाह करेगा? बस, जहां एक बार नियंत्रण ढीला हुआ महकमे की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है, कोई भी मुलाज़िम अपने असली काम में ज़रा भी रुचि नहीं लेता। सबका ध्यान फ़रियादियों और अपराधियों की जेबों पर ही रहता है।

जब थाने-चौकियों की नीलामी का सिलसिला चल पड़े तो फिर सीनियर-जूनियर की तमीज़ भी खत्म कर दी जाती है। थानों में इन्सपेक्टर को एसएचओ लगाने की बजाये जब सब इन्सपेक्टर लगाये जाते हों खास कर मलाईदार थानों में तो गड़बड़ी का होना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, कमाऊ पूत यदि जूनियर भी है तो उसे एसएचओ तथा सीनियर को उसके मातहत लगा दिया जाता है। इन हालात में विभागीय अनुशासन, निष्ठा व कर्त्तव्यपरायणता की मुलाज़मान से उम्मीद करना निरर्थक है। सभी लोग टाइम टपाने और जेब भरने की जुगत में रहते हैं। जनता की सुरक्षा जाये भाड़ में।

हाऊस टैक्स दुबारा लगाने पर सरकार की किरकिरी

नगर निगम की साख इतनी कमजोर हो चुकी है कि किसी भी बैंक और वित्तीय संस्था उसे कर्ज देने को तैयार नहीं हुई। हां, गुड़गांव की बनी नई-नई नगर निगम ने जरूर कुछ धन बतौर कर्ज (जो कभी लौटाया नहीं जा सकेगा) दिया जो कि अब तक हजम किया चुका है। नगर निगम ने जब अपनी हिस्सेदारी नहीं दी तो केंद्र सरकार ने अर्बन रिन्यूवल स्कीम के तहत ग्रांट भी नहीं दिया। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने नगर निगम पर दबाव बढ़ाया।

नगर निगम की हालत ऐसी है कि दुनिया भर के तमाम टैक्सों को लेने और अपनी जायदादों को बेच खाने के बावजूद उसका अपना पेट ही नहीं भरता। विभिन्न मदों में टैक्सों के रूप में लिया जाने वाला सारा धन निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर ही खर्च हो जाता है। महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा कर पाने में धन की कमी सदैव आड़े आती है। निगम ने ऐसे-ऐसे सफेद हाथी पाल रखे हैं कि उसकी सारी आमदनी चट कर जाते हैं और फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाते। अवैध कमाइयों का तो कोई हिसाब ही नहीं है, जो उन्हें वैध रूप में मिलता है, वह भी बेहिसाब है। फिर भी निगम को अपनी परियोजनाओं को पूरा कर पाना असंभव-सा दिखाई पड़ता है और निगम के उच्चाधिकारियों की यह कोशिश होती है कि किस तरह जनता पर नया टैक्स लादा जाये। इस बार जब केंद्र सरकार ने अपनी ग्रांट बंद कर दी तो निगम को समाप्त किया गया हाऊस टैक्स फिर से बहाल करने का अच्छा बहाना मिल गया। उसने राज्य सरकार पर अपना दबाव बढ़ा दिया और केंद्र सरकार ने हुड्डा को एक अच्छा बहाना दे दिया हाऊस टैक्स को बहाल करने का।

अब जब हाऊस टैक्स दुबारा शुरू किया जायेगा तो जनता में रोष होना स्वाभाविक है, पर इससे निगम को क्या मतलब है? वह तो अधिसूचना जारी होते ही हाऊस टैक्स वसूलने में लग जायेगी। हां, इसका खामियाजा हुड्डा एवं उनकी सरकार को भुगतना पड़ेगा। भूलना नहीं होगा कि हुड्डा ने चुनावी वादे के तहत हाऊस टैक्स को समाप्त करवाया था। लेकिन अब उसके दुबारा चालू होने की स्वीकृति देने पर जनता यह पूछ रही है कि जब हाऊस टैक्स दुबारा शुरू ही किया जाना था तो आखिर इसे समाप्त क्यों करवाया गया था?

नगर निगम के अब तक के क्रिया कलापों से स्वत: सिद्ध है कि इसे पैसा चाहे कितना ही मिल जाये, केंद्र सरकार के अलावा वर्ल्ड बैंक भी अपना सारा खज़ाना इसे दे दे तो भी ये कुछ भी विकास कार्य करने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि न तो इनमें योग्यता है, न क्षमता है, न निष्ठा है, न काम करने की इच्छा है। लक्ष्य है तो एक ही है अधिक से अधिक लूट। इनको पैसा देना रेत में घी डालने के समान है। इस नगर निगम को पैसे की नहीं, सख्ती से हांकने वाले की जरूरत है।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का तमाशा

इन मैचों में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए और दर्शकों के दिलों को गुदगुदाने के लिए चीयर गर्ल्स का सहारा लिया गया है। ये अधनंगी लड़कियां मैदान के किनारे मौजूद रहती हैं और खिलाड़ियों द्वारा लगाये गये हर चौके-छक्के पर डांस कर उनका हौसला बढ़ाती हैं। दर्शक इस पर अश्लील फ़ब्तियां कसते हैं, पर इन्हें कोई परवाह नहीं, बल्कि ये इस बात से और खुश ही होती हैं कि उन्हें फ़ब्ती कसने लायक तो समझा गया। शुरू में इन चीयर्स गर्ल्स को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई। उनका कहना था कि खेल के मैदान पर अधनंगी लड़कियों का नाच किसी तरह से उचित नहीं है। इस पर तर्क दिया गया कि विदेशों में चीयर्स गर्ल्स का मैचों में होना आम बात है। यह भी कहा गया कि विदेशों में बड़ी-बड़ी हस्तियों ने एक दौर में चीयर्स गर्ल की भूमिका निभाई है। इसके बाद मामला ठंडा हो गया। आईपीएल वाले पैसे की गर्मी में किसी की कुछ भी नहीं सुनते। कहा तो यहां तक जाता है कि ये चीयर्स गर्ल्स मैचों के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह तो बढ़ाती ही हैं, एकांत में खेल आयोजकों और खिलाड़ियों की शरीर-सेवा भी करती हैं। अब पता नहीं, इन बातों में कितनी सच्चाई है! बहरहाल, इन खेलों में इतनी अश्लीलता और गंदगी है कि यहां कुछ भी हो सकता है। विदेशी लड़कियों के नाच के अलावा यहां दर्शकों को मैदान पर अनलिमिटेड शराब भी परोसी जा रही है। दर्शक जाम टकराते हैं और मदमस्त हो कर खेल देखते हैं। इस पर कुछ आपत्तियां भी आईं तो आती रहें, शराब परोसी ही जा रही है। इस मामले में आबकारी वाले चुप क्यों बैठे हैं? क्या आयोजकों को मैदान में शराब परोसने के लाइसेंस दिये गये हैं? अगर लाइसेंस दिये गये हैं तो इससे बुरी बात कुछ भी नहीं हो सकती। फ़िर तो पैसे वाले लोग़ जो चाहें करें, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा।

वैसे सरकार को चाहिए कि इस पूरे तमाशे पर ही रोक लगाये। पर सरकार रोक क्यों लगायेगी? वह तो उन्हीं लोगों की है जो इसे चला रहे हैं। दूसरे सरकार में शामिल शरद पवार इसके समर्थक हैं जिनका इस खेल से पुराना संबंध रहा है। इस तरह, खेल के नाम पर अश्लीलता और धन के प्रदर्शन का दौर अभी जारी रहेगा।

पाठक मंच

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। इस अख़बार में पुलिस और प्रशासन व्यवस्था के बारे में सच को सामने लाया जाता है। पानीपत में डीएसपी जैसा पुलिस अधिकारी लुटेरा बन कर व्यवसायियों को लूटने में लगा हुआ था, यह सच आपने जिस रूप में लाया था, और किसी मीडिया ने ऐसा नहीं किया। इस अंक में भी आपने पुलिस के अंदर के लुटेरों पर जम कर प्रहार किया है। यह सच है कि अगर अफ़सरों और नेताओं का संरक्षण न मिले तो कोई लूट-मार न कर सके। पर अफ़सरों और नेताओं को लुटेरा अधिकारी ही पसंद आता है, क्योंकि माल भी वही खिलाता है। आपने सप्रमाण जो कुछ लिखा है, वह आंखें खोल देने वाला है। नक्सलवाद पर आपकी टिप्पणी अच्छी लगी। अंक में प्रकाशित अन्य लेख भी अच्छे लगे। अगले अंक करा इंतजार है।

- पंकज कुमार, फरीदाबाद

मज़दूर मोर्चा का अंक मिला। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अपराधों को बढ़ावा देने में पुलिस की भूमिका बहुत ही ज़्यादा है और स्वयं पुलिस में भी लुटेरे अफ़सर भारी संख्या में हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पुलिस ने अपराधियों पर काबू पा लिया होता। पर पुलिस वाले ही अपराधियों को संरक्षण प्रदान करते हैं और विभाग में भी लुटेरों को तरजीह देते हैं। इस अंक में नक्सलवाद की समस्या पर और खापों पर लिखा लेख काफ़ी अच्छा लगा, वैसे अन्य लेख भी कड़वी सच्चाइयों को सामने लाने वाले हैं।

- मानसी, गुड़गांव

मज़दूर मोर्चा के इस अंक में पुलिस से संबंधित जो सच्चाई आपने सामने लाई है, वह आंखें खोलने वाली है। यह पूरी तरह सच है कि अगर अफ़सर और नेता अपराधियों को संरक्षण न दें तो अपराधों पर पूरी तरह लगाम लग सकती है। पर यहां तो आम अपराधियों को छोड़ें, स्वयं पुलिस में ही अपराधियों का जमावड़ा लगा हुआ है। नक्सलवाद के संबंध में हमारी यह सोच थी कि ये राष्ट्रविरोधी और आतंकवादी तत्व हैं, पर आपके लेख को पढ़ने से यह लगा कि ये ग़रीबों का भला करने वाले काम कर रहे हैं और सरकार लोगों को गुमराह करने के लिए इन्हें बदनाम करती है। इस अंक में प्रकाशित सभी समाचार और लेख पसंद आये।

- आलोक कुमार, पलवल

मज़दूर मोर्चा का अंक मिला। मैंने शुरू से लेकर अंत तक सारे समाचार और लेख पढ़ लिये। इस अंक को पढ़ने से यह पता चला कि किस तरह अफ़सर अपने फ़ायदे के लिए विभाग में ही डकैत पुलिसकर्मियों को तरजीह देते हैं। यह सच है कि लोगों में पुलिस की छवि बहुत ही खराब है।

इसका कारण है पुलिस को लुटेरी भूमिका में सामने आना। इस पर नियंत्रण कौन करेगा, यह समझ में नहीं आता।

पुलिस के पास इतने अधिकार हैं कि वह मनमानी करती है। अगर अफ़सर और नेता सच्चरित्र एवं ईमानदार हों तभी स्थिति में सुधार हो सकता है, वरना पूर्ववत स्थिति बरकरार रहेगी। नक्सलवाद के उभरने का कारण गरीबों का अंतहीन शोषण है, इस बात से मैं सहमत हूं। आप इस तरह के लेख और भी छापें। व्यावसायिक मीडिया सारी सच्चाई को सामने नहीं लाता।

- अरविंद पाठक, बल्लबगढ़

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। इसमें आपने सही लिखा है कि पुलिसिया डकैत अफ़सरों के संरक्षण में ही पलते हैं। अफ़सर क्या, ऐसे डकैतों को नेताओं का भी खुला संरक्षण हासिल होता है। अगर अफ़सरों और नेताओं का खुला संरक्षण इन्हें प्राप्त न हो तो यक डकैत पल ही नहीं सकते।

सवाल है, जो अधिकारी स्वयं ही विभाग में डकैत पालते हों, वे अन्य अपराधियों को क्या पकड़ेंगे? यही कारण है कि आज अपराधी खुलेआम नग्न नृत्य कर रहे हैं। उन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। यह आपका ही अख़बार है जो स्पष्ट शब्दों में पुलिस की सच्चाई को सामने ला रहा है, वर्ना मीडिया में इस तरह बेख़ौफ़ हो कर लिखने वाला कोई नहीं है। नक्सलवाद के बारे में भी आपने सही लिखा है कि यहां ग़रीब से ग़रीब को ही शासक वर्गों द्वारा लड़ाया जा रहा है। अंक में प्रकाशित दूसरे लेख भी कड़वी सच्चाइयों को सामने लाते हैं। खाफ पंचायतों के बारे में जो लिखा गया है, पूरी तरह सच है।

- राम प्रसाद, फरीदाबाद

कुछ तथ्य

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2008 के अनुसार, देश में कम से कम 23 हज़ार और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता है।

बहुचर्चित भोर समिति की सिफारिशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रत्येक 20,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 27,000 लोगों पर मात्र एक चिकित्सक उपलब्ध है। इनमें 81 प्रतिशत चिकित्सक शहरों में हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा अभी भी झोलाछाप डॉक्टरों के हवाले है।

परमाणु ख़तरा

अति घातक परमाणु बिजली घरों के लिये आतुर भारत सरकार यूरेनियम के लिए हाथ-पैर मार रही है। इस संदर्भ में लोगों के भारी विरोध के बावजूद मेघालय में यूरेनियम के खनन की तैयारी की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है। यूरेनियम और इसके कचरे के वर्तमान और भविष्य में घातक प्रभावों को जानते खासी छात्रों ने इसका व्यापक विरोध शुरू कर दिया है।